

पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०

मुख्यमंत्री ने 'कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2018' को सम्बोधित किया

मुख्यमंत्री ने यू०पी०सी०एस०आर० वेब पोर्टल का उद्घाटन किया

देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में राजकीय प्रयास के अलावा उद्योग जगत की बड़ी भूमिका : मुख्यमंत्री

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से उद्योग जगत द्वारा अनेक सामाजिक कार्य किए जाते हैं

अनेक क्षेत्रों में सी०एस०आर० के माध्यम से जनहितकारी सुविधा के विकास की बड़ी सम्भावनाएं

समन्वय तथा सहभागिता से जन कल्याणकारी गतिविधियों के अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं

पर्यटन स्थलों में सुविधाओं के विकास के लिए उद्योग जगत द्वारा सी०एस०आर० से योगदान किया जा सकता है

संस्कृत विद्यालयों की मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा इनमें आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सी०एस०आर० फण्ड से कार्य कराया जा सकता है
16 महीनों में 1.35 करोड़ शौचालय निर्माण से उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान

राज्य सरकार के सतत प्रयास, टीम वर्क तथा हर क्षेत्र की सहभागिता से प्रधानमंत्री आवास योजना में उ०प्र० को प्रथम स्थान

मुख्यमंत्री को रेडिको खेतान के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री ललित खेतान ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 51 लाख रुपए का चेक प्रदान किया

लखनऊ : 11 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में राजकीय प्रयास के अलावा उद्योग जगत की बड़ी भूमिका है। लोक कल्याण को समर्पित कार्यक्रमों के संचालन में उद्योग जगत पारम्परिक रूप से योगदान करता रहा है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से उद्योग जगत द्वारा अनेक सामाजिक कार्य किए जाते हैं। जनसामान्य द्वारा भी धर्मार्थ, लोक कल्याण के कार्य किए जाते हैं। समन्वय तथा सहभागिता से

इन जन कल्याणकारी गतिविधियों के अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में आयोजित 'कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2018' में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने यू0पी0सी0एस0आर0 वेब पोर्टल का उद्घाटन भी किया। यह पोर्टल कॉरपोरेट तथा अन्य व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रदेश में सी0एस0आर0 परियोजनाओं के चयन तथा वित्त पोषण हेतु एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस मौके पर रेडिको खेतान के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री ललित खेतान ने मुख्यमंत्री जी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 51 लाख रुपए का चेक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेशवासियों की सतत समृद्धि में कॉरपोरेट तथा अन्य व्यक्तियों के सहयोग की शक्ति के महत्व को प्रदेश सरकार भलीभांति समझती है। इसमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह पहली बार यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में जनसहभागिता से कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिक उद्देश्यपरक और प्रभावी बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 02 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत दो प्रकार के कार्यक्रम, सामान्य साफ-सफाई की व्यवस्था तथा बेस लाइन सर्वे के अनुसार शौचालय से वंचित परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराना था। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण प्रदेश के लिए यह बड़ी चुनौती थी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण के समय प्रदेश के 43 प्रतिशत परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय थे। राज्य सरकार के विगत डेढ़ वर्षों के सतत प्रयास से वर्तमान में 96 प्रतिशत

परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने 02 अक्टूबर, 2018 तक बेस लाइन सर्वे के व्यक्तिगत शौचालय से वंचित सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराकर प्रदेश को ओडी0एफ0 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पिछले वर्ष 44 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इस वर्ष के 09 महीनों में 90 लाख शौचालय बनवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक शौचालय के लिए 12 हजार रुपए की राशि निश्चित की गई है। ग्रामवासियों को शौचालय के उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश की 59 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में एक स्वच्छाग्रही नियुक्त किया गया है। इस अभियान की सफलता के लिए 02 लाख 25 हजार राज मिस्त्रियों को शौचालय निर्माण के लिए प्रशिक्षित कर अभियान से जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप इस अभियान में उत्तर प्रदेश आज देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता में लोगों की सहभागिता और सहयोग का लाभ भी मिला है। इससे विगत 16 महीनों में राज्य सरकार 1.35 करोड़ शौचालय बनाने में सफल हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने 11 लाख ग्रामीण तथा 04 लाख शहरी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु 01 लाख 20 हजार रुपए आवास का स्वयं निर्माण करने पर लाभार्थी को मनरेगा के माध्यम से 90 दिन की मजदूरी तथा शौचालय के लिए 12 हजार रुपए दिए गए हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था सी0एस0आर0, जिला खनिज निधि आदि से भी की गयी है। शहरी क्षेत्र में लाभार्थी को आवास हेतु ढाई लाख रुपए तथा शौचालय हेतु 20 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत शौचालय हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार जब सत्ता में आयी थी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना नहीं थी। राज्य सरकार

के सतत प्रयास, टीम वर्क तथा हर क्षेत्र की सहभागिता से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को पांच पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। यहां पर धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, ईको पर्यटन आदि के अनेक स्थल हैं। इन स्थलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आध्यात्मिक, बौद्ध, राम, कृष्ण, सूफी आदि सर्किट तथा स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना संचालित हैं। पर्यटन स्थलों तथा स्मारकों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं यथा पेयजल, सौर प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, घाटों के नवीनीकरण, पार्कों के सौन्दर्यीकरण, पर्यटकों के लिए शेड, बायो टॉयलेट निर्माण आदि में उद्योग जगत द्वारा सी0एस0आर0 के तहत योगदान किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा अन्य अनेक क्षेत्रों में सी0एस0आर0 के माध्यम से जनहितकारी सुविधा के विकास की बड़ी सम्भावनाएं हैं। ग्रामीण इलाकों में खेल के मैदान का विकास, खेल के सामान की उपलब्धता, व्यायामशाला, वेलनेस सेण्टर आदि के विकास में सी0एस0आर0 उपयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह कार्य छोटे होकर भी व्यापक परिवर्तनकारी साबित हो सकते हैं। यह लोगों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार शहरी इलाकों में पार्कों का सौन्दर्यीकरण, जिम, वेलनेस सेण्टर का निर्माण कराया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभ्य समाज की व्यवस्था समाज की सोच पर निर्भर करती है। इस सोच को सकारात्मक रूप से विकसित किया जा सकता है। अस्पतालों में तीमारदारों के लिए रुकने की व्यवस्था, टॉयलेट, पेयजल व्यवस्था, जेल के मुलाकातियों के लिए शेल्टर, पेयजल, टॉयलेट आदि व्यवस्थाएं भी सी0एस0आर0 के माध्यम से करायी जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम से कौशल विकास के क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। प्रदेश के विकास खण्डों में, वहां की

आवश्यकता के अनुरूप कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना से युवाओं को स्वावलम्बन की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों के भवन काफी पुराने हैं। इन भवनों के पुनर्निर्माण, मरम्मत तथा संस्कृत विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास में भी सी0एस0आर0 फण्ड बड़ा योगदान कर सकता है।

कार्यक्रम में अपने स्वागत सम्बोधन में मुख्य सचिव श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि राष्ट्र निर्माण एक जन अभियान होना चाहिए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। इसके लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर उन कार्यों की सूची उपलब्ध है, जिनमें उद्योग जगत तथा सामान्य जन द्वारा सहयोग किया जा सकता है।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पंचायतीराज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री राजेश कुमार सिंह, कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (सी0एस0आई0) की यू0पी0 स्टेट काउन्सिल के चेयरमैन एवं एम0के0यू0लि0 के चेयरमैन श्री मनोज गुप्ता, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एफ0आई0सी0सी0आई0) यू0पी0 के पूर्व चेयरमैन एवं के0एम0 ग्रुप के सी0एम0डी0 श्री एल0के0 झुनझुनवाला, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आई0आई0ए0) के प्रतिनिधि श्री मनमोहन अग्रवाल सहित उद्योग जगत के अन्य प्रतिष्ठित उद्यमी उपस्थित थे।